



04 - पेरिस समझौते से
अनेकों के बाह्य
निकलने का अर्थ



05 - उग्नेका अधिकार :
आपकी ताकत, आपकी
पहचान

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 24 दिसंबर, 2024



भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-114 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रु.- 2 (डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)



06 - किसान नई कशत मिट्टी
का परीक्षण, रासायनिक
खाद मिट्टी से छीन रहे...



07 - बेट ऑफ फ़िव योजना
एमपी बोर्ड में फ़िर लागू

खबर

खबर

प्रसंगवाणी

डेढ़ अरब वाले भारत में और बच्चे पैदा करने की मांग क्यों?

सौतिक बिस्वास

Sुकर राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, पिछले साल चीन का पीछे छोड़कर भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी रखता देश बन गया।

करीब 1.45 अरब लोगों की आबादी के साथ, आप सोच रहे रहे होंगे कि देश अब और अधिक बच्चे पैदा करने पर चुप्पी साध लेगा। लेकिन इस मामले में बहस अचानक और तेज़ हो गई है। दो दक्षिणी राज्यों अंधे प्रदेश और तमिलनाडु के नेताओं ने हाल ही में अब बच्चे पैदा करने की वकालत की।

गिरावं जनमर्द और बुजुर्ग होती आबादी का हवाला देते हुए अंधे प्रदेश प्राप्तसाफ्ट देने के बारे में सोच रहा है। राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में दो बच्चों की नीति को भी रख कर दिया और रिपोर्ट में कहा गया है कि पड़ोसी तेलंगाना राज्य भी निकट भविष्य में ऐसा ही कर सकता है। एक अन्य पड़ोसी राज्य तमिलनाडु भी इसी तह के बल्कि और बढ़ा-चढ़ाकर किए जाने वाले दावे कर रहा है।

भारत की प्रजनन दर में काफ़ी कमी आई है और 1950 में प्रति महिना 5.7 के मुकाबले यह गिरकर मीजूदा समय में दो रह गई है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 17 में प्रजनन दर प्रति महिना दो जन्म के प्रतिस्थापन स्तर से भी नीचे चली गई है। (प्रजनन दर जब 2.1 पर पहुंची है तो उसे 'प्रिलेसमेंट लेवल फर्टिलाई' कहा जाता है। इस आकड़े तक पहुंचने का मतलब होता है कि अगले तीन से चार दशक में देश की आबादी स्थिर हो जाएगी।)

पांच दक्षिणी राज्य भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले प्रतिस्थापन स्तर के प्रजनन दर को हासिल करने में काफ़ी आगे हैं। केरल ने यह उपलब्धि 1988 में, तमिलनाडु ने 1993 में और बाकियों ने 2000 के

दशक के मध्य तक हासिल कर ली थी। आज, पांच दक्षिणी राज्यों की कुल प्रजनन दर 1.6 से नीचे है, जिनमें कर्नाटक की प्रजनन दर 1.6 और तमिलनाडु की 1.4 है। दूसरे शब्दों में, इन राज्यों में प्रजनन दर अधिकांश योग्यता देशों के बराबर है या उनसे भी कम है। लेकिन इन राज्यों को डर है कि अलग-अलग राज्यों में आबादी के अंतर के साथ भारत की बदलती जनसांख्यिकी निश्चित रूप से चुनावी प्रतिनिधित्व, संसदीय सीटों के राज्यवार आवटन और सकारी राजस्व में हस्तेदारी पर असर लालेगी। इंटरेशनल इंजीट्रूट पर यांत्रिक सार्वजनिक साइरेस में जनसांख्यिकी के प्रोफेसर श्रीनिवास गोली ने कहा, 'बेहतर अर्थिक प्रदर्शन और संघीय राजस्व में अच्छा खासा योगदान देने के बावजूद उन्हें अपनी असरदार जनसंख्या नियन्त्रण नीति के लिए दिलत किए जाने का डर है।'

दक्षिणी राज्य एक अन्य बड़ी चिंता से जूझ रहे हैं क्योंकि 1976 के बाद भारत, 2026 में पहली बार परिसीमन की तैयारी कर रहा है। ये कावायद आबादी में बदलाव को प्रतिविवत करने के लिए चुनावी परिसीमा को फिर से निर्धारित करेंगे, जिससे अर्थिक रूप से संपर्क दक्षिणी राज्यों की संसदीय सीटों में कमी आने की संभावना है। चूंकि सरकारी राजस्व को राज्य की आबादी के लिहाज से आवटित किया जाता है, इसलिए कई राज्यों को डर सत्ता रहा है कि इससे वर्तनी अधिक परेशानी हो जाएगी। जनसांख्यिकी विशेषज्ञ के एस जैसं और उमा भूषण कृति का अनुमान है कि परिसीमन से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे घरी आबादी वाले उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी जबकि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों को नुकसान हो जाएगा।

पांच दक्षिणी राज्य भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले प्रतिस्थापन स्तर के प्रजनन दर को हासिल करने में काफ़ी आगे हैं। केरल ने यह उपलब्धि 1988 में, और बाकियों ने 2000 के

सकता है और इससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में और बदलाव आएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने संकेत दिया है कि राजस्व हिस्सेदारी और संसदीय सीटों के आवटन को लेकर जलदबाजी नहीं की जाएगी। जनसांख्यिकी विशेषज्ञों के मुताबिक, मुख्य चुनावी है कि प्रजनन दर गिरने के साथ ही भारत की आबादी तेज़ी से बढ़ी हो रही है। आबादी के बढ़े होने की इस तेज़ रफ़तार का संबंध, प्रजनन गिरावट में भारत की अनोखी देशों में भी है। लेकिन भारत में भारतीय देशों में, जीवनस्त और शिक्षा में सुधार और शहरीकरण व्यापारिक रूप से प्रजनन को कम कर देता है क्योंकि बच्चों के जीवित रहने में सुधार होता है। लेकिन भारत में मामूली सामाजिक और आर्थिक प्राप्ति के बावजूद प्रजनन दरों में तेज़ी से गिरावट दर्ज की गई, इसका कारण आकामक परिवार नियोजन कार्यक्रम थे, जिन्हें लक्ष्य, प्रोत्साहन और हतोत्साहित करने वाले उपायों के माध्यम से छोटे परिसीमों को बढ़ावा दिया। गोली कहते हैं कि, इसके कुछ अनप्रेक्षित नीतियों भी हुए। अंश प्रेसर की प्रजनन दर 1.5 है जो स्थूल के बराबर है, लेकिन इसकी प्रति व्यक्ति आय उससे 28 गुना कम है। बढ़ते कर्ज और सीमित संसाधनों के साथ क्या इस तरह के राज्य एक तेज़ी से बढ़ी होती आबादी के लिए ऊंची पेंशन या सामाजिक सुरक्षा मूल्या करा सकते हैं? इस पर सोचना की आवश्यकता है।

संयुक्त राज्य नांसंख्या को प्रति व्यक्ति आय उससे 40 गुना धन वितरण के मामले में आवट के निचले 20 प्रतिशत में आते हैं। गोली कहते हैं, 'भारत अमीर होने से पहले ही ग्रीष्म रहे रहा है।'

कम बच्चों का मतलब बुद्धावस्था निर्भरता अनुपात में बढ़ोत्तरी भी है, जिससे बढ़ी बुजुर्ग आबादी की देखभाल करने वालों की संख्या भी कम होती है।

जनसांख्यिकी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत की स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक केंद्र और ओल्ड एज होम्स इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। शहरीकरण, प्रवासन, और बदलाव से श्रम बाज़ार भी परामर्शक प्रावित्रिक स्पोर्ट को और अधिक कमज़ोर कर रहे हैं जो भारत का मजबूत पक्ष रहा है, इससे और अधिक बुजुर्ग पीछे लटक रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जनसांख्यिकी के विशेषज्ञ टिम डायरसन ने बताया कि एक या दो दशक बाद, 'प्रजनन का बहुत कम स्तर का बने रहना, आबादी में तेज़ी से कमी का कारण बनेगा।' प्रति महिला 1.8 जन्म की प्रजनन दर, धीमी रफ़तार और आबादी में स्तुलन लायक कमी का कारण बनती है। लेकिन 1.6 या उससे कम कम 'तेज़, जनसंख्या में बेकाबू गिरावट' का द्विग्राम रहे रहते हैं। बहुत कम संख्या में लोग प्रजनन और अमीर रूप से सकारात्मक आवादी के लिए ऊंची पेंशन या सामाजिक सुरक्षा मूल्या करा सकते हैं? इस पर सोचना की आवश्यकता है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

पीएम मोदी ने 71 हजार को ज्वाइनिंग लेटर बांटे

कहा- डेढ़ साल में करीब 10 लाख पक्की नौकरी दी पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित किया गया था, जिसमें 51 हजार से ज्यादा

सोपानवार को देश के 45 जातियों पर आयोजित रोजगार

लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया था।



विकसित भारत पर भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा है और लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है, क्योंकि भारत में हर तेज़ी और हर निर्णय के केंद्र में भारत का प्रतिभासली युवा है। आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियमित हो रहा है।

रोजगार में कठोर दूसरे वर्ष के लिए नियमित हो रहा है। अब तक 14 मेलों में 9.22 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। इससे पहले 29 अक्टूबर 2024 को

मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और परदर्शिता के साथ दी जा रही हैं। किसी भी देश के विकास उत्तरी युवाओं के लिए नौकरी दी जानी चाहिए।

रोजगार में कठोर दूसरे वर्ष के लिए नियमित हो रहा है। अब तक 14 मेलों में 9.22 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। इससे पहले 29 अक्टूबर 2024 को

मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और परदर्शिता के साथ दी जा रही हैं। किसी भी देश के विकास उत्तरी युवाओं के लिए नौ

